International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 4; Issue 1; January 2018, Page No. 78-79

संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका खाड़ी युद्ध के संदर्भ में

डॉ. सी. के. भगत
राजनीति विज्ञान विभाग, बिरसा कॉलेज खूँटी, राँची विश्व विद्यालय, राँची, झारखण्ड, भारत

सारांश
विश्व में तेल उत्पादक खाड़ी देशों का विशेष महत्व है। तेल उत्पादक देश ईराक, ईरज, कुवैत, सउदी अरब प्रमुख देशों के अलावा संयुक्त राज्य अमीरात, तर्की, लेबबानान, बहरीन, सीरीया, इजराइल, कतर भी शामिल है। इन देशों के पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिम में भूमध्य सागर और यूरोपीय देश दक्षिण में अरब सागर, अदन तथा मध्य में फारस की खाड़ी है। पूर्व और पश्चिम एशिया में तेल सम्पदा को लेकर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाती है। तेल के कारण ही अपना प्रभाव को उस क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास सभी बड़े–राष्ट्रों के द्वारा की जाती है और यही उस क्षेत्र में परस्पर प्रतिद्वन्दिता का कारण हो जाती है। इसी कारण शीत युद्ध और सैन्य स्पर्धा का भी केन्द्र हो गया और इसी के फलस्वरूप पश्चिमी एशिया खाड़ी युद्ध की ओर बढ़ने लगा। 21 अगस्त 1990 में खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का बिगुल बज गया था जबकि इसकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपनी सीमा से लगे तेल क्षेत्रों से तेल को निकालने का आरोप कुवैत के ऊपर लगाया। इराक द्वार इस तेल चोरी के आरोप और सीमा विवाद का आधार बनाकर 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अमेरिका द्वारा कुवैत के ऊपर आक्रमण में कुवैत के पत्र में आ जाने पर इसका स्वरूप बदल गया और यह युद्ध इराक–अमेरिका का हो गया। कुवैत की ओर से अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशो ने युद्ध में भाग लिया और इराक अकेले इन राष्ट्रो का सामना किया। इस युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है।

मूल शब्दः संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, तेल उत्पादक, शीत युद्ध

प्रस्तावना
खाड़ी युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 28 फरवरी 1991 को समाप्त हुई जिसकी शुरूआत 2 अगस्त 1990 में ईराक द्वारा कुवैत पर किये गये आक्रमण से प्रारम्भ हुआ था।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन जिसमें चौंतीस राष्ट्र संयुक्त राज्य के नेतृत्व में ईराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया था और इस युद्ध का उद्देश्य 2 अगस्त 1990 को ईराक द्वारा कुवैत पर किये गये आक्रमण और कब्जे के बाद कुवैत से इराकी बलो को बाहर निकालना था।

शोध प्रविधि
प्रस्तुत शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति की है। शोध आलेख के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों प्रकार के स्त्रोंतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः प्रकाशित ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

कुवैत पर इराकी आक्रमण
तेल पर ईराक का ज्यादातर राजस्व निर्भर था। इराक तेल की ऊँची कीमत को बनाए रखना चाहता था जिससे वह ईराक–इरान के बीच युद्ध से अपने कर्ज की अदायगी सुनिश्चित कर सके।

परन्तु जब तेल की कीमते गिर गई तो कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को कीमतों में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कच्चे तेल के अधिक उत्पादन के कारण कीमतों के गिरावट का जिम्मदार ठहराया।

इराक का कहना था कि जब वह ईरान–ईराक युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा था उस समय कुवैत ने सैन्य और तेल सुविधाओं का निर्माण इराक के क्षेत्र पर किया।

इस कारण अपने कर्ज को माफ करने की मांग इराक ने कुवैत से किया परंतु कुवैत ने इराक के मांग के दोष को पूरी तरह निराधार बतलाया।

दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर संघर्ष तेज हो गया और कुवैत की सीमा पर सैनिक तैनात करना इराक द्वारा शुरू कर दिया।

ईराकी सेना जो कि कुवैत की सीमा के पास इकट्ठी थी अप्रत्याशित रूप से 2 अगस्त 1991 को कुवैत की राजधानी, कुवैत नगर पर बमबारी करके आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण के फलस्वरूप हवाई अड्डों और दो सैन्य हवाई अड्डो पर कब्जा कर लिया।

कुवैत के अधिकांश सशस्त बलों को दो दिनों के युद्ध के पश्चात्, इसकी रियब्लिकन गार्ड के द्वारा भगा दिया गया या पड़ोस के सऊदी अरब की ओर भाग गय। इराक की निर्णायक जीत के बाद, 8 अगस्त 1991 को इराक ने कुवैत को अपना 19 वॉ प्रान्त घोषित किया गया और सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अली हसन अल मजिद (केमिकल अली) को कुवैत का सैन्य गर्वनर बना दिया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका खाड़ी युद्ध में
इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के कुछ घंटो के भीतर, खाड़ी संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव ''पैरेज द कुडयार'' के द्वारा आक्रमण को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया। साथ ही सुरक्षा परिषद ने कड़ी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पारित किये जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव 660 को पास किया गया जिसमें 2 अगस्त 1990 को इराकी हमले की कड़ी निन्दा करते हुए इराक तत्काल और बिना शर्त अपनी सैनिक कुवैत से हटा ले। अरब लीग के द्वारा भी 3 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी गयी और लीग के भीतर से होने वाले संघर्ष में समाधान के लिए कहा गया।

इराक ने संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव की उपेक्षा करते हुए कुवैत से बाहर नहीं निकला फलस्वरूप 6 अगस्त को प्रस्ताव 661 पारित किया गया जिसके द्वारा इराक पर व्यापारिक आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाने के लिए सदस्य देशों को बाध्य किया गया।

इराक द्वारा कुवैत के कब्जे की अमान्यता की घोषणा करने वाले संकल्प 662 का प्रस्ताव 9 अगस्त को पारित हुआ जिसमें सदस्य देशों को कहा कि वे कुवैत को हड़प करने की इराकी कार्यवाही को मान्यता न दें।

युद्ध के बीच विदेशी नागरिकों को वहाँ से जाने की अनुमति और सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से 18 अगस्त को सुरक्षा परिषद् से प्रस्ताव 664 पारित करते हुए यह मांग की गयी थी कि इराक विदेशी नागरिकों को इसकी सुविधायें प्रदान करें और साथ ही इस बीच कोई ऐसी कार्यवाही न करें जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पहुँचे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 25 अगस्त को पारित प्रस्ताव 665 के द्वारा इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध पर बल देने के लिए नौ सैनिक नाकाबंदी का अधिकार दिया गया। इस नौ सैनिक नाकाबंदी में अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैनाओं ने इस तरह से नाकेबंदी की कि इराक तथा कुवैत से न कोई चीज बाहर जा सकती थी और न अन्दर आ सकती थी इसके फलस्वरूप खाद्य सामग्री का अभाव इराक और कुवैत में हो गया था।

इराक में खाद्य सामगी भेजने की छुट के लिए प्रस्ताव संख्या 666 सितम्बर 13 को इस शर्त पर दी गयी कि संयुक्त राष्ट्र रेडक्रास की देख रेख में इसका वितरण होगा।

कुवैत में विदेशी दूतावासो और उनके कर्मचारियों पर इरानी सेना द्वारा की गयी कार्यवाही की भर्त्सना 6 दिसम्बर को प्रस्ताव संख्या 668 के द्वारा की गई।

प्रस्ताव संख्या 670 द्वारा हवाई उड़ान रोकने का निर्णय 25 सितम्बर को लिया गया। साथ ही इराकी जहाजों का विदेशी बन्दरगाहों में आने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

कुवैत में इराकी सेनाओं और अधिकारियों की मानवीय अधिकार का व्यापक स्तर पर उल्लंघन की पुष्टि प्रस्ताव संख्या 674 द्वारा 29 अक्टूबर को की गई।

शांतिपूर्ण समाधान की तलाश

आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से इराक को कुवैत से बाहर निकालने पर जोर दिया गया और इस तरह से इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला गया।

इराक द्वारा अपने आक्रमण को प्रमाणित करने के लिए इस समस्या को मध्य–पूर्व के शांति के मुद्दे के साथ–साथ सुलझाया जाना चाहिए।

खाड़ी युद्ध से उत्पन्न इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संविधान संघ ने कई प्रयास किये।

इराक ने सैन्य संघर्ष से बचने और राजनीतिक समाधान तलाशने की फ्रांस राष्ट्रपति मिटरैंड द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

परन्तु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों को मानते हुए कुवैत से हटाने के निर्णय पर कोई बदलाव नहीं किया।

सुरक्षा परिषद् संकल्प 678 का अधिनियम

कुवैत पर सद्दाम हुसैन के इराक द्वारा आक्रमण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों की एक श्रृंखला के तहत 29 नवम्बर 1990 को प्रस्ताव संख्या 678 पारित किया गया, जिसमें इराक को कुवैत से अपनी सेना हटाने का अंतिम समय निर्धारित कर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने इराक को यह चेतावनी दी कि यदि वह 15 जनवरी 1990 तक कुवैत से नहीं हट जाता है तो उसे हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य देश सभी तरह के आवश्यक तरीको का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बल प्रयोग भी शामिल है।

प्रस्ताव 678 को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर और ईराक के विदेश मंत्री अब्दुल तारिक अजीज के बीच हुई बैठक का भी कोई निशचित परिणाम नहीं मिल पाया।

कुवैत से इराक की वापसी की तय समय सीमा से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज दी कुइयार ने बगदाद का दौरा कर इराकी राष्ट्रपति हुसैन को मनाने के लिए अंतिम प्रयास किया।

फिर भी राष्ट्रपति हुसैन ने कुवैत से इराकी सेना की वापसी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं दिखलाई दी।

संकल्प 678 द्वारा निर्धारित समय सीमा के आगमन के बाद भी इराक ने वापसी का कोई भी संकेत नहीं दिया। तब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक के विरूद्ध हवाई अभियान 17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरूआत करते हुए इराक की तेल रिफाइनीयों के सुरक्षा और अन्य बुनियादी ढ़ाँचें पर बमबारी के साथ की गई।

इराक के द्वारा सऊदी अरब और इजरायल में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर अपनी कम दूरी की स्क्ड मिसाइलों से इसका जवाब दिया गया।

डेजर्ट स्टॉर्म एक हवाई और नौसेनिक हमला था इसके पाँच दिन बाद ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की शुरूआत की गई।

इस तरह से शान्ति के प्रयासों के विफल हो जाने के पश्चात् अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना ने लम्बी लड़ाई के पश्चात् इराक को कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।

निष्कर्ष

युद्ध किसी भी समस्या का अन्तिम समाधान नहीं होता है। युद्ध से केवल युद्धरत राष्ट्रों को ही नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों के ऊपर इसका प्रत्यन्न और अप्रत्यज्ञ प्रभाव पड़ता है।

खाड़ी युद्ध अमेरिका की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस युद्ध में सर्वोत्तम शक्तिशाली राजय के रूप में अमेरिका का विश्व में उभर हुआ और युद्ध के फलस्वरूप इराक आर्थिक और सैनिक सन्धियों से जकड़ दिया गया।

बहुराष्ट्रीय सेना ईराक में तब तक मौजुद रहेंगी जब तक राष्ट्र संघ के सारे प्रस्ताव लागू नहीं हो जाती और इसका उल्लघंन होने पर आक्रमण की कार्यवाही करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था।

युद्ध में इराक को अपनी हार के बाद विभिन्न प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ा और सामूहिक विनाश के किसी भी परमाणु या रासायनिक हथियारों को रखने से रोका गया।

युद्ध से सैन्य और नागरिक जीवन पर इसके प्रभाव के कारण इस अपराध की गंभीरता से निंदा की गई।

परन्तु खाड़ी युद्ध की अवधि संक्षिप्त थी, इसमें जीवन के नुकसान के अलावा युद्ध समाप्त होने के बाद भी स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है।

खाड़ी युद्ध इराक और कुवैत के बीच का युद्ध था जिसमें युद्ध को रोकने का संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा प्रयास किये गये। परन्तु यह युद्ध नहीं रोका जा सका जिसके फलस्वरूप विश्व समुदाय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया।

फिर भी यह युद्ध विकराल रूप धारण नहीं कर पायी और अन्ततः 28 फरवरी 1991 को युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध से युद्धरत दोनों प्रमुख राज्य इराक और कुवैत तबाह हो गये। परन्तु इस युद्ध के फलस्वरूप विश्व पटल पर अमेरिका का उभार एक सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुई।

संदर्भ सूचि

1. वर्मा दीनानाथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
2. प्रतियोगिता दर्पण मई 1991
3. डॉ फड़िया वी.एल. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
4. प्रतियोगिता किरण अप्रैल 1993
5. मनोरमा इयर बुक वर्ष 1992
6. दैनिक समाचार पत्र– हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण